



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]
No. 358]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2008/असाधा 10, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2008/ASADHA 10, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2008

सं. 30/2008-सेवाकर

सा.का.नि. 489(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 73(अ) के साथ पठित धारा 94 की उपधारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (I) इन नियमों को सेवाकर (सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की) नियमावली, 2008 कहा जायेगा।
2. ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तित होंगे।

2. परिभाषायें - (I) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम से तात्पर्य वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय-V से है।

(ख) "विचाराधीन राजस्व" से तात्पर्य ऐसे किसी भी सेवाकर से है जो न तो लगाया गया है और न ही उसका भुगतान किया गया है या अल्प रूप से लगाया या भुगतान किया गया है या गलती से जिसको वापस कर दिया गया है जिसके बारे में धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 73 क की उपधारा (3) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(ग) "सम्पत्ति" में अचल सम्पत्ति भी शामिल है

(घ) "निजी सम्पत्ति" से अभिप्राय ऐसे किसी भी चल या अचल सम्पत्ति से है जो कि प्रोप्राइटर, या साझीदार या निदेशक के स्वामित्व में है जिसका व्यापारिक क्रियाकलाप से कोई प्रयोजन नहीं है।

(ड.) " धारा " से अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।

2. इन नियमों में प्रयुक्त अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में, या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में इनके लिये दिया गया है और यदि ऐसे शब्दों या अभिव्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) में या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में परिभाषित किया गया है तो इनका अर्थ वही होगा जो इस अधिनियम या नियमों में दिया गया है।

3. सम्पत्ति के अनन्तिम कुर्की से संबंधित प्रक्रिया- (1) इस अधिनियम की धारा 73 या 73 'क' के अंतर्गत किसी प्रक्रिया के चलते रहने के दौरान यदि सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इस बात से संतुष्ट है कि राजस्व संबंधी हित की सुरक्षा के लिये ऐसा करना जरूरी या समीचीन है कि ऐसे किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क किया जाना चाहिए जिसे इस अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) और धारा 73क की उपधारा (3) के अंतर्गत नोटिस जारी कर दी गई है, तो वह तथ्यों और परिस्थितियों का विधिवत सत्यापन करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क कराने के लिए इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पास प्रस्ताव करेगा।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्रस्ताव को प्राप्त करने पर, या अपनी ओर से, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसे अनन्तिम कुर्की को न्याय संगत ठहराती हैं तो, ऐसे व्यक्ति को अनन्तिम कुर्की के लिये नोटिस जारी करेगा, जिसमें इन नियमों के अंतर्गत ऐसी कार्यवाई किये जाने के कारण और अनन्तिम रूप से कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा भी दिया गया होगा, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को यह अवसर देते हुए कि ऐसे नोटिस के जारी होने के दिनों के भीतर इस बारे में अपना बचाव कर सके।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से या व्यक्तिगत रूप से की गई पेशी पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क करके लिए लिखित रूप में आदेश जारी करेगा।

बशर्ते कि प्रोप्राइटरों या भागीदारों या निदेशकों जैसी भी स्थिति हो, की वैयक्तिक सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

4. सम्पत्ति, जिसको कुर्क किया जा सकता है- (1) सम्पत्ति की अनन्तिम कुर्की उसी हद तक की जायेगी जिस हद तक यह राजस्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक होगी अर्थात् कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का मूल्य ऐसे व्यक्ति के खिलाफ विचाराधीन राजस्व के अनुपात, यथा सम्भव नजदीक से नजदीक, में होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की अचल सम्पत्ति को केवल तभी कुर्क किया जायेगा यदि कुर्की के लिए उपलब्ध अचल सम्पत्ति इतनी पर्याप्त नहीं है कि इससे राजस्व हित की सुरक्षा की जा सके।

5. ऐसे व्यक्ति का दायित्व जिसकी सम्पत्ति अनन्तिम रूप से कुर्क की गयी है- जहाँ किसी सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति या उसका कोई प्रतिनिधि कुर्क की गई

सम्पत्ति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना अन्य किसी भी प्रकार से न तो बंधक कर सकता है, न पट्टे पर दे सकता है, न स्थानांतरित कर सकता है, न इसका उपदान या इसके साथ अन्य कोई संव्यवहार कर सकता है।

6. अवधि, जब तक सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की का आदेश लागू रहता है:- (1) नियम 3 के उपनियम (3) के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के अनुपालन की तिथि से 6 माह की अवधि के बीत जाने पर प्रत्येक अनंतिम कुर्की का प्रभाव समाप्त हो जायेगा।

बशर्ते कि मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ऐसे किसी कारण से जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, उक्त अवधि को उतने समय तक बढ़ा सकता है जितना वह उचित समझे, बशर्ते कि इस प्रकार बढ़ाई जाने वाली कुल अवधि किसी भी मामले में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसी अनंतिम कुर्की तब समाप्त हो जायेगी जब उक्त व्यक्ति विचाराधीन राजस्व की राशि को ब्याज समेत वापस कर देता है।

[फा. सं. 237/120/2006-सीएक्स 4]

आशिमा बंसल, अवर सचिव

प्रपत्र

((देखें नियम 3(1))

नाम और अन्य व्यौरों को प्रकाशित करने हेतु प्रस्ताव को अवधारित करने संबंधी प्रपत्र

1. निर्धारिती या व्यक्ति का नाम और पता:
2. सेवाकर कोड सं. (एस टी सी) या पंजीकरण सं. (यदि कोई हो):-
3. निर्धारिती का स्वरूप

(प्रोप्राइटरशिप या भागीदारी या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, या पंजीकृत न्याय या सोसाइटी या अन्य (स्पष्ट करें):

4. आयुक्तालय :
5. प्रभाग :
6. कारण बताओ या मांग नोटिस का ब्यौरा:
7. कारण बताओ नोटिस में निहित धनराशि:
8. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की का कारण:
9. सम्पत्ति का पता और अन्य ब्यौरा:
10. सम्पत्ति का मूल्य जिसको कुर्क किये जाने का प्रस्ताव है:

11. पिछले अपराधों का ब्यौरा, यदि कोई हो:

12. टिप्पणी, यदि कोई हो:

दिनांक:

सहायक आयुक्त या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
या सेवाकर का हस्ताक्षर
(नाम और सरकारी मुहर सहित)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2008

No. 30/2008-Service Tax

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 read with section 73C of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Service Tax (Provisional Attachment of Property) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994);

(b) "pending revenue" means any service tax that has not been levied or paid or has been short-levied or paid or erroneously refunded in respect of which a notice has been served under sub-section (1) of section 73 or sub-section (3) of section 73 A;

(c) "property" includes immovable property;

(d) "personal property" means any movable or immovable property belonging to a proprietor or partner or director, which is not in relation to business activity;

(e) "section" means a section of the Act;

(2) Other words and expressions used in these rules shall have the meaning assigned to them under the Act or rules made thereunder or if such words or expressions are not defined in the Act but defined in the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, they shall have meaning assigned to them in that Act or the rules made thereunder.

3. **Procedure for provisional attachment of property.** — (1) If the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, is satisfied that it is necessary or expedient, for the purpose of protecting the interest of revenue, during the pendency of any proceeding under section 73 or section 73A of the Act, to attach provisionally any property belonging to a person on whom a notice has been served under sub-section (1) of section 73 or sub-section (3) of section 73A of the Act, shall after due verification of the facts, and the circumstances of the case, forward a proposal for provisional attachment of property of such person, to the Commissioner of Central Excise, in the format annexed to these rules.

(2) The Commissioner of Central Excise, on receipt of proposal as specified in sub-rule (1), or on his own, if he is satisfied that circumstances of case justify provisional attachment, may cause service of a notice on such person for provisional attachment, with reasons for initiating action under these rules and the details of property to be attached provisionally, giving opportunity to such person to make submissions in this regard, within fifteen days of service of such notice.

(3) Upon consideration of submissions made by such person, in writing or in person or both, the Commissioner of Central Excise may pass an order in writing to attach provisionally any property belonging to such person:

Provided no such order shall be issued to attach the personal property of Proprietor or Partners or Directors, as the case may be.

4. **The property that can be attached-** (1) The provisional attachment of property shall be to the extent it requires to protect the interest of revenue, that is to say, the value of property attached shall be of value as nearly as may be equivalent to that of the amount of pending revenue against such person.

(2) The movable property belonging to such person shall be attached only if the immovable property available for attachment is not sufficient to protect the interest of revenue.

5. **Obligations of person whose property has been attached provisionally** Where a property has been provisionally attached, the said person or his representative shall not mortgage, lease, transfer, deliver or deal with the attached property in any manner except with the previous approval of the Commissioner of Central Excise.

6. **Period for which order of provisional attachment of property remains in force-** (1) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of six months from the date of the service of the order passed under sub-rule (3) of rule 3.

Provided that the Chief Commissioner of Central Excise may, for reasons to be recorded in writing, extend the aforesaid period by such further period as he thinks fit, provides that the total period of extension shall not in any case exceed two years.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), every such provisional attachment shall cease to have effect when the said person pays the pending revenue alongwith interest thereon.

[F. No. 137/120/2006-CX, 4]

ASHIMA BANSAL, Under Secy.

FORMAT

[See rule 3(1)]

Proforma for forwarding the proposal for publishing of names and other details

- 1. Name and address of the assessee or person:**
- 2. Service Tax Code (STC) No. or Registration No. (if any):**
- 3. Constitution of assessee:**
(Proprietorship or Partnership or Private Ltd or Public Ltd or Registered Trust or Society or Other (specify))
- 4. Commissionerate:**
- 5. Division:**
- 6. Details of show cause or demand notice:**
- 7. Amount involved in the show cause notice:**
- 8. Reasons for provisional attachment of property.**
- 9. Address and other details of property;**
- 10. Value of property proposed to be attached:**
- 11. Details of previous offences, if any:**
- 12. Comments, if any:**

Date:

**Signatures of Assistant or Deputy Commissioner of
Central Excise or Service Tax
(With name and official seal)**